रणजीत टाइम्स

इंदौर

गुरुवार, 12 फरवरी, 2026

वर्ष 02 | अंक 41 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

'गेहूं-चावल से दूध-दही तक कृषि क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित', India-US ट्रेड डील पर वाणिज्य सचिव का बड़ा बयान

नई दिल्ली। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौतों में हमेशा उन क्षेत्रों को लेकर 'स्पष्ट सोच' रखी है जो देश के लिए 'बेहद' संवेदनशील हैं और अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते में ऐसे सभी प्रमुख क्षेत्रों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष संयुक्त बयान को कानूनी समझौते में बदलने पर काम कर रहे हैं, जिसे मार्च के अंत तक अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। यहां मीडिया से बात करते हुए वाणिज्य सचिव ने कहा, 'भारत ने हमेशा सभी समझौतों पर स्पष्ट सोच के साथ बातचीत की है।

भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते में संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित

जो भी क्षेत्र भारत के लिए बेहद संवेदनशील हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे किसान, मछुआरे, दुग्ध क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, वहां हमने अपने साझेदार देशों को साफ बता दिया है कि भारत ऐसे मामलों में बाजार नहीं खोल सकता या पहुंच नहीं दे सकता।' उन्होंने कहा, 'अगर आप पिछले एक साल में किए गए सभी समझौतों को देखें। हमने पांच व्यापार समझौते किए हैं। सभी में संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा की गई है। अमेरिका के साथ भी सभी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है। जहां थोड़ी संवेदनशीलता थी, वहां हमने शुल्क दर 'कोटा' व्यवस्था का इस्तेमाल किया ताकि बाजार तक पहुंच सीमित रहे और हमारे किसानों पर असर न पड़े।'

कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित

इस महीने की शुरुआत में घोषित अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथनाल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे संवेदनशील कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा है। इन वस्तुओं पर अमेरिका को कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है। ये उत्पाद संवेदनशील हैं क्योंकि इनका संबंध देश के छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका से है।

अन्य मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भी भारत ने संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है। भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को अंतिम रूप दिया है। भारत को 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 1.6 अरब डालर रहा। प्रमुख निर्यातों में बादाम (छिलके सहित, 86.8 करोड़ डालर), पिस्ता (12.1 करोड़ डालर), सेब (2.1 करोड़ डालर) और एथनाल (एथिल अल्कोहल, 26.6 करोड़ डालर) शामिल हैं। देश का निर्यात जनवरी में सकारात्मक रहने की उम्मीद वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक आर्थिकअनिश्चितताओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के वस्तु एवं सेवा निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है और जनवरी में भी इसके सकारात्मक रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि जनवरी के निर्यात आंकड़े इस महीने जारी किए जाएंगे। अग्रवाल ने यहां कहा, 'कुल मिलाकर निर्यात अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वस्तु निर्यात में हम मजबूती से टिके हुए हैं। सेवाएं हमेशा की तरह बहुत अच्छा कर रही हैं। आप जनवरी के आंकड़ों के सकारात्मक रहने की उम्मीद कर सकते हैं।' वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-दिसंबर दौरान देश का वस्तु निर्यात 2.44 प्रतिशत बढ़कर 330.29 अरब डालर रहा। वाणिज्य मंत्रालय को उम्मीद है कि 2025-26 में वस्तु एवं सेवा निर्यात 850 अरब डालर को पार कर सकता है जो 2024-25 में 825 अरब डालर रहा था।

वीबीएसए बिल की जांच के लिए संसदीय समिति का हुआ गठन, भाजपा की पुरंदेश्वरी होंगी अध्यक्ष

नई दिल्ली। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) विधेयक की जांच करने के लिए भाजपा सदस्य डा. पुरंदेश्वरी की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इसके जरिये उच्च शिक्षा नियामक स्थापित करने का प्रयास करना है।

लोकसभा सचिवालय की मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, यह समिति दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनी है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले यह समिति प्रस्तावित कानून के प्रविधानों की जांच करेगी। शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया गया वीबीएसए विधेयक उच्च शिक्षा नियामक ढांचे में सुधार करने का प्रयास करता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है। यह प्रस्तावित कानून कई मौजूदा नियामकों को एक एकल समग्र निकाय से बदलने और मान्यता, वित्तपोषण और मानक निर्धारण कार्यों के पृथक्करण की व्यवस्था प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। राज्यसभा में सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर (भाजपा), सुधांशु त्रिवेदी (भाजपा), प्रदीप कुमार वर्मा (बीजद), मीना कुमारी जैन (भाजपा), दिग्विजय सिंह (कांग्रेस), सागरिका घोष (तृणमूल कांग्रेस), सस्मित पात्रा (बीजद), एम.थंबिदुराई (एआइएडीएमके), संजय कुमार झा (जदयू) व राम गोपाल यादव (सपा) शामिल हैं। लोकसभा सदस्यों में डा. पुरंदेश्वरी (भाजपा), भारत्रुहरी महताब (भाजपा), संबित पात्रा (भाजपा), तेजस्वी सूर्या (भाजपा), अनुराग सिंह ठाकुर (भाजपा), बांसुरी स्वराज (भाजपा), विवेक ठाकुर (भाजपा), हेमांग जोशी (भाजपा), ब्रिजमोहन अग्रवाल (भाजपा), वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (कांग्रेस), अंगोमचा बिमोल अकोइजाम (कांग्रेस), वामसी कृष्ण गडुम (कांग्रेस),आदि।

भारत बंदः पश्चिम बंगाल सरकार का कड़ा रुख, अनुपस्थित कर्मचारियों का कटेगा वेतन

कोलकाता। राज्य सचिवालय नबान्न ने 12 फरवरी को 24 घंटे के राष्ट्रव्यापी हड़ताल (भारत बंद) के आह्वान का कड़ा विरोध किया है। वित्त विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालय यहां तक कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यालय भी उस दिन खुले रहेंगे और सभी कर्मचारियों को काम पर आना होगा।

अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 12 फरवरी (गुरुवार) को किसी भी कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा, चाहे वह आधे दिन का हो या पूरे दिन का। यदि उस दिन अनुपस्थिति मानी जाती है, तो उसे अस्थायी अनुपस्थिति माना जाएगा और उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में छूट दी गई है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, 11 फरवरी से पहले गंभीर बीमारी के कारण छुट्टी पर है, या 11 फरवरी से पहले

स्वीकृत बाल देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश या अर्जित अवकाश पर है, तो उसकी अनुपस्थिति स्वीकार्य मानी जा सकती है। हालांकि, ऐसे मामलों में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त, यदि कोई कर्मचारी 12 फरवरी को बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहता है, तो विभाग प्रमुख या नियंत्रक प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। यह भी सूचित किया गया है कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि इस आदेश को लागू करने की सभी प्रक्रियाएं 28 फरवरी तक पूरी कर ली जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट वित्त विभाग को भेज दी जानी चाहिए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के श्रम सुधारों और व्यापक आर्थिक नीतियों के विरोध में गुरुवार, 12 फरवरी को पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अशोकनगर

श्रीमती शुभ्रता त्रिपाठी द्वारा

गोलू यादव

आवेदक आयुष्मान नामदेव पिता जगदीश मोहन नामदेव निवासी ग्राम शाढोरा द्वारा केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।उक्त आवेदन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक को केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया।

दीवार में दबने से किसान की मौत
मवेशी बाधनें के दौरान हुआ हादसा

प्रदीप सिंह बघेल

शहडोल। ब्यौहारी थाना क्षेत्र के आखेटपुर गांव में मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे में 53 वर्षीय किसान की मौत हो गई। किसान मवेशी को घर के पास स्थित एक पुराने सार की दीवार में बांध रहा था तभी उसी समय अचानक दिवाल गिरने से उसके नीचे दब गया, जिससे उसकी जान चली गई। घटना से गांव में शोक की लहर है। पुलिस के अनुसार आखेटपुर निवासी अयोध्या कोल पिता स्व. रामप्यारे कोल मंगलवार सुबह रोज की तरह मवेशियों को जंगल चराने ले गए थे। देर शाम करीब 7 बजे वे मवेशियों को लेकर घर लौटे और उन्हें सार में बांधने लगे। एक मवेशी को उन्होंने दिवाल में लगे लोहे के सहारे बांध दिया था। इसी दौरान मवेशी ने अचानक जोरदार झटका दिया और रस्सी छुड़ाने की कोशिश की। झटके के कारण कमजोर दिवाल अचानक भरभराकर किसान के ऊपर गिर गई।

दिवाल के मलबे में दबने से अयोध्या कोल गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। आनन-फानन में अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ब्यौहारी थाना प्रभारी जिया उल हक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बुधवार सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।इस दुखद घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में मातम पसरा हुआ है और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की है।

किताब पर रार, पेंगुइन ने कहा... छपी ही नहीं ,राहुल का सवाल, पब्लिशर झूठा या नरवणे?

गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्रा का बाथरूम में मिला शव

पूर्व आर्मी चीफ की पुस्तक को लेकर आमने-सामने सरकार और विपक्ष मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कई घरों में लगाई आग महू में रेलवे विकास के लिए हटाया गया अतिक्रमण पुलिस कमिश्नर इंदौर ने 19 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित महू में बेरछा गांव के पास दिखे दो तेंदुए, ग्रामीणों में दहशत मथुरा में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी, परिवार के पांच लोगों ने जहर खाया आबकारी विभाग झाबुआ ने 2 लाख से अधिक की अवैध शराब की जप्ती की सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित पुलिस अपनी ही कार्रवाई में घिरी, नाबालिग को जेल भेजने पर विवाद शिक्षा के प्रति कैदी का लगाव, पुलिस सुरक्षा में दी 12वीं की परीक्षा ट्रैफिक प्रहरी अभियान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सुप्रीम कोर्ट में चुनावी याचिकाओं पर टिप्पणी राजेंद्र शुक्ला को पुष्पांजलि अर्पितa

जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न दो चरणों में होगी जनगणना

प्रदीप सिंह बघेल

शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई है। कलेक्टर ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने और सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना अधिकारी श्री गिरीश शुक्ला ने बताया गया कि भारत की जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। जनगणना का प्रथम चरण 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। जनगणना 2027 का दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। दुसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। मकान सूचीकरण के कार्य के लिए स्वगणना का विकल्प 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक प्रथम चरण के पूर्व 15 दिन तक उपलब्ध रहेगा। मकान सूचीकरण के कार्य में प्रगणक और पर्यवेक्षक द्वारा

शासन द्वारा अधिसूचित 33 सवाल पूछे जाएगें।

उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी, 2027 में होगा। जनसंख्या की गणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी साथ ही व्यक्तियों के सम्बन्ध में अन्य विभिन्न बिन्दुओं जैसे- आयु,लिंग,वैवाहिक स्थिति, धर्म, दिव्यांगता, मातृभाषा, साक्षरता, शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक क्रियाकलाप, प्रवास, प्रजननता विवरण इत्यादि पर जानकारी एकत्रित की जाएगी। जनगणना 2027 देश की प्रथम डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें अप्लीकेशन के माध्यम से आंकड़ो का संकलन किया जाएगा। जनगणना के समस्त कार्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग सेन्सस् मैनेजमेन्ट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, निवासियों को अपना जनगणना डेटा स्वयं ऑनलाइन भरने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वगणना वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। आगामी जनगणना वर्ष 1872 से 16वीं एवं स्वतंत्रता के बाद की 08वीं जनगणना होगी। जनगणना से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का निष्पादन जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। जनगणना के दौरान संकलित व्यक्तिगत जानकारियाँ पूर्णतः गोपनीय होती हैं और इसे किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया जाता है साथ ही, एकत्रित की गई व्यक्तिगत जानकारी को कहीं पर भी साक्ष्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। जनगणना 2027 के प्रगणक, पर्यवेक्षक या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के ओटीपी या बैंक डिटेल्स की मांग नहीं की जाएगी। जनगणना के डिजिटल टूल्स 1. आंकड़ों का संग्रहण-अ. मकान सूचीकरण ऐप (हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन्स,) ब . जनगणना ऐप (पॉपूलेशन इनूमरेशन, स्व गणना पोर्टल 3. सेन्सस् मैनेजमेन्ट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल 4. हाउस लिस्टिंग ब्लाक क्रिएटर वेब मैप ऐपजनगणना 2027 के लिए मास्टर ट्रेनरों द्वारा फिल्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। फील्ड ट्रेनरों द्वारा प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को 03 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनगणना 2027 में भाग लेने वाले प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को शासन द्वारा मानदेय भी दिया जाएगा।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, डीआईओ श्री मधुकर सिंह, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री आनन्द राय सिन्हा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अमरनाथ सिंह, जिला योजना अधिकारी श्री अहिरवार, सहायक परियोजना अधिकारी डूडा श्रीमती मीनाक्षी शुक्ला, सहित जिला जनगणना समन्वय समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहें।

ब्यौहारी पुलिस की तत्परता ने दिखाया असर 12 घंटे के भीतर दोनों नाबालिग पहुचें सुरक्षित घर

प्रदीप सिंह बघेल

ब्यौहारी क्षेत्रांतर्गत दिनांक 10.02.26 और 11/02/26 को दो अलग अलग शिकायतों में दो नाबालिग के गुम हो जाने की सूचना प्राप्त होते ही ब्यौहारी पुलिस द्वारा संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए दो अलग-अलग मामलों में अपहृत नाबालिग बालकों को मात्र 12 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया है। घटना का विवरण - दिनांक 10-11.02.2026 की दरम्यानी रात थाना ब्यौहारी में दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गईं -

प्रथम प्रकरणः फरियादी द्वारा रिपोर्ट सूचना देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका 12 वर्षीय पुत्र लापता है व रिश्तेदारों व परिचितों के यहां पता करने पर भी कहीं नहीं मिल रहा।

द्वितीय प्रकरणः फरियादिया ने रिपोर्ट दी कि उनका 12 वर्षीय पुत्र लापता है व गांव में सभी जगह तलाश की पर नहीं मिल रहा संबंधी व

रिश्तेदारों के यहां भी पता लगाने पर नहीं मिला रहा।

दोनों ही मामलों में ब्यौहारी पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ब्यौहारी के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी और सघन तलाश शुरू की। पुलिस की सक्रियता का परिणाम रहा कि सूचना मिलने के मात्र 12 घंटे के भीतर दोनों नाबालिग बालकों को रेलवे स्टेशन ब्यौहारी से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया। दस्तयाबी उपरांत बालकों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुरक्षित सौंप दिया गया है, जिससे दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है।

सराहनीय भूमिका- इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में : निरीक्षक जियाउल हक, थाना प्रभारी, ब्यौहारी के नेतृत्व में सउनि. गया प्रसाद कन्नौजे, प्र.आर. नरेन्द्र सिंह, प्र.आर. हीरा सिंह, प्र.आर. हरपाल सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

रणजीत टाइम्स

अंधे कत्ल का खुलासा: नागपुर आउटर और यार्ड रोड के बीच मिला था महिला का शव

शादी की जिद करने पर प्रेमिका की हत्या, आरोपी बिहार से गिरफ्तार

रणजीत टाइम्स

पुलिस ने एक माह पुराने सनसनीखेज अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। नागपुर आउटर और यार्ड रोड के बीच पेड़ के नीचे मिली अज्ञात महिला के शव के मामले में आरोपी रिजवान को बिहार के रोहतास जिले के रामपुर भरेथा से गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को एसपी साईं कृष्णा एस थोटा ने एसडीओपी कार्यालय में प्रेसवार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया।

6 जनवरी 2026 को नाला मोहल्ला के आविद खान ने यार्ड रोड पर अज्ञात महिला का शव मिलने की रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई। एसपी और अतिरिक्त एसपी के निर्देश पर एसडीओपी इटारसी वीरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। एसपी ने बताया कि टीम ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। साइबर सेल ने तकनीकी डेटा का विश्लेषण किया। मुखबिरों की टिप पर बिहार के थाना कच्छवा, रामपुर भरेथा पहुंची टीम ने रिजवान उर्फ रिजवान पिता नेहलउद्दीन खान को खेत से पकड़ा। गहन पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया।पूछताछ में पता चला कि रिजवान और मृतका रिहाना खातून पड़ोसी गांवों के थे। दोनों 1-2 माह से चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में रह रहे थे। रिहाना शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन रिजवान तैयार नहीं। उसे शक था कि रिहाना का किसी और से संबंध है। 4 फरवरी को चंद्रपुर से इटारसी पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर झगड़ा हुआ। रिहाना ने गांव जाकर रिपोर्ट करने की धमकी दी तो रिजवान ने उसे फ्रेश होने के बहाने सुनसान यार्ड रोड पर ले जाकर हत्या कर दी। पुलिस ने रिजवान को कोर्ट में पेश कर 12 फरवरी तक रिमांड ले ली है।

इनकी सराहनीय भूमिका, 30 हजार का इनाम

एसपी ने टीम को बधाई दी। अहम भूमिका निभाने वालों में आरक्षक राजकुमार झपाटे (749), आरक्षक संदीप यदुवंशी (साइबर सेल), थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला इटारसी थाने का समस्त स्टाप, एसडीओपी कार्यालय का समस्त स्टाप, थाना प्रभारी पथरोटा संजीव पवार, साइबर सेल नर्मदापुरम, आरपीएफ इटारसी के आरक्षक निर्मल पटेल व प्रहलाद कुमरे और रक्षित केंद्र हरदा के मनीष मेहतो शामिल हैं। आईजी ने टीम को 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया।प्रेसवार्ता में एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा, थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला और पथरोटा थाना प्रभारी संजीव पवार मौजूद रहे।

बस संचालकों को पुराने बस स्टैंड पर 5 मिनट के स्टॉप के लिए देना होगा शपथ पत्र

रणजीत टाइम्स

शहर के पुराने बस स्टैंड से सवारी चढ़ाने वाली बसों को अब 5 मिनट का स्टॉप मिल जायेगा, लेकिन प्रशासन की शर्तें मानना अनिवार्य रहेगा। मंगलवार को नवीन रेस्ट हाउस में विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा की मौजूदगी में नपाध्यक्ष पंकज चौरे और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच करीब पौन घंटे चली बैठक में यह फैसला लिया गया। यात्रियों, ग्रामीणों, छात्र-छात्राओं और व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने स्टैंड पर 5 मिनट रुकने का निर्णय हुआ, लेकिन शर्तों का पालन न करने पर परमिट रद्द हो जाएगा।बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रिंकू शर्मा, एसडीएम नीलेश शर्मा, एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष राहुल चौरे, ग्रामीण अध्यक्ष मयंक मेहतो और भाजपा नेता जयकिशोर चौधरी उपस्थित रहे। पुराने बस स्टैंड बंद होने के बाद सभी बसें नए स्टैंड से चल रही हैं, जिससे स्थानीय छात्रों, ग्रामीणों और यात्रियों को ऑटो से जाना पड़ रहा है या ब्रिज तिराहे पर इंतजार करना पड़ रहा। इसी मुद्दे पर कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से सड़क पर उतरकर 5 मिनट स्टॉप की मांग कर रही थी कांग्रेस ने ज्ञापन भी सौंपा था और हस्ताक्षर अभियान चलाकर आंदोलन की तैयारी कर रही थी। सोमवार देर शाम विधायक डॉ. शर्मा के साथ व्यापारियों व बस संचालकों की बैठक में प्रारंभिक सहमति बनी थी, जो मंगलवार को अंतिम रूप ले चुकी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रिंकू शर्मा ने बताया कि शिकायतों और छात्र-छात्राओं, ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए अगले सात दिनों तक बसों का पांच मिनट स्टॉप पुराने बस स्टैंड पर दिया गया है।लेकिन इस पांच मिनट में पुराने बस स्टैंड के अंदर आने और जाने का समय भी शामिल रहेगा। बस सिर्फ दो मिनट के लिए रुकेगी और यात्रियों को बैठाकर या उतारकर आगे रवाना होगी। यह व्यवस्था अगले सात दिन तक रहेगी। इसके लिए बस संचालकों को एक शपथ पत्र देना होगा, साथ ही प्रशासन की शर्तों का पालन करना होगा। सात दिन तक अगर शर्तों के अनुसार बसें चलेंगी तो इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा।

पेट्रोल पंप मालिक को रॉड-डंडों से पीटा, हत्या का प्रयास; 3 बोलेरो जब्त, 8 पर केस

रणजीत टाइम्स

चक्कर रोड स्थित पेट्रोल पंप के मालिक मनु प्रताप सिंह और उनके रिश्तेदार शुभेक्षु तोमर पर रेत कारोबार से जुड़े आधा दर्जन से अधिक लोगों ने सुबह 11 बजे लोहे की रॉड व डंडों से हमला कर दिया। रेत रॉयल्टी को लेकर हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। हमले से ट्रैफिक जाम हो गया, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले।एडिशनल एसपी अभिषेक राजन ने बताया कि फरियादी शुभेक्षु तोमर व मनु प्रताप सिंह पेट्रोल पंप पर खड़े थे। तभी तीन बोलेरो से रेत कारोबार से जुड़े कुछ लोग आए और पंप के पास पड़े रेत के ढेर की रॉयल्टी मांगने लगे। फरियादी पक्ष ने सवाल किया कि पूछने का अधिकार क्या है, तो बहस भड़क गई। हमलावरों ने रॉड-डंडों से हमला कर तीनों को घायल कर दिया।पुलिस ने राजा, सुरेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, नेत्रपाल, नागेंद्र कुमार, आकाश शर्मा व नरेंद्र सिंह सहित 8 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज किया। तीन बोलेरो जब्त कर ली गईं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

कोचिंग शिक्षक संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान डीजे पर लगे लगाम

रणजीत टाइम्स

प्रदेशभर में शुरू हो चुकी बोर्ड परीक्षाओं के बीच बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने पर मंडीदीप कोचिंग शिक्षक संघ ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार थाना मंडीदीप में एसडीएम महोदय के नाम से आवेदन देकर शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे कान फोड़ू डीजे, लाउडस्पीकर आदि पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

शिक्षक संघ का कहना है कि 10 फरवरी से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि 14 फरवरी से कक्षा 10वीं की परीक्षाएं भी प्रारंभ होने वाली हैं। ऐसे में विवाह मुहूर्त के चलते माता पूजन, बारातों और मैरिज गार्डनों में तेज आवाज में डीजे बजाने की प्रथा से छात्रों की एकाग्रता और पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

वहीं व्यवसाई संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि डीजे की तेज आवाज से न केवल पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बल्कि जहां से बारात या डीजे गुजरते हैं, वहां दुकानों में रखा सामान भी तेज कंपन से गिरने लगता है। इससे स्थानीय व्यापारियों और निवासियों को भी परेशानी हो रही है। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से मंडीदीप कोचिंग शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रह्मानंद नायक, उपाध्यक्ष सोम पाल, कोषाध्यक्ष अनूप यादव, वरिष्ठ शिक्षक सीता राम सर सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। शिक्षक संघ ने विद्यार्थियों के हित में तत्काल प्रभाव से ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने और सख्ती से नियम लागू करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कई जिलों में पहले से ही बोर्ड परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास 100-200 मीटर तक लाउडस्पीकर/डीजे पर रोक लगाई जा चुकी है, ऐसे में मंडीदीप में भी इसी तरह के आदेश की अपेक्षा की जा रही है। गोहरगंज एसडीएम सीएस श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में थाना स्तर पर डीजे संचालकों की बैठक बुलाकर, नियमानुसार दिशा निर्देश जारी करेंगे, इसके बाबजूद नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

एक कलाकार की पुकार और इंडस्ट्री का मौन

राजपाल यादव प्रकरण पर विशेष संपादकीय

संपादकीय – गोपाल गावंडे

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में जब रोशनी होती है तो सब दिखाई देते हैं, लेकिन जब अंधेरा आता है तो चेहरों की पहचान बदल जाती है। आज चर्चा एक ऐसे अभिनेता की है जिसने वर्षों तक लोगों को हँसाया-पर जब खुद पर संकट आया तो चारों ओर सन्नाटा पसर गया। सपना, जोखिम और असफलता की कीमत साल 2010 में राजपाल यादव ने निर्माता बनने का साहस किया। उनकी फिल्म अता पता लापता लगभग 11 करोड़ की लागत से बनी। इसके लिए उन्होंने एक निजी कंपनी से 5 करोड़ का ऋण लिया।

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। निवेश डूबा, कर्ज बढ़ा, और मामला अदालतों तक जा पहुँचा। निचली अदालत से होते हुए केस दिल्ली उच्च न्यायालय पहुँचा। अदालत ने भुगतान की समयसीमा तय की, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे शर्तें पूरी न हो सकीं। आखिरकार आत्मसमर्पण का आदेश-और जेल। यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, एक कलाकार के टूटते आत्मविश्वास की कहानी है।

अदालत में कही गई वे पंक्तियाँ... "मेरे पास पैसे नहीं हैं, साथ देने वाला कोई नहीं... जेल भेज दीजिए।" यह शब्द केवल बयान नहीं, उस इंडस्ट्री के आईने हैं जहाँ संघर्ष के दिनों में साथ रहने वाले, सफलता के दौर में तस्वीरें खिंचवाने वाले-मुश्किल समय में मौन हो जाते हैं।

कौन आया साथ?

सबसे पहले बिहार के उद्योगपति राव इंद्रजीत यादव ने सहयोग की घोषणा की। फिर अभिनेता सोनू सूद ने एक भविष्य प्रोजेक्ट के साइनिंग अमाउंट के रूप में मदद की पहल की। मीडिया जगत से उपेंद्र राय ने भी सहयोग राशि घोषित की। परंतु सवाल यह है

क्या यह जिम्मेदारी केवल बाहरी समाज की है? क्या फिल्म उद्योग, जो सैकड़ों करोड़ की कमाई करता है, अपने कलाकारों के लिए कोई संरचना नहीं बना सकता?

बॉलीवुड की चुप्पी-असंवेदनशीलता या डर?

हो सकता है कानूनी जटिलताएँ हों।

हो सकता है मामला व्यक्तिगत हो। पर जब एक कलाकार अकेलेपन की बात करे, तो संवेदना तो दिखाई जा सकती है। बॉलीवुड में अक्सर "फैमिली" शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या यह परिवार केवल अवॉर्ड फंक्शन और प्रमोशन तक सीमित है?

जरूरी प्रश्न

क्या फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों के लिए "आपातकालीन सहायता कोष" नहीं होना चाहिए?

क्या असफलता को अपराध समझ लिया गया है? क्या रिश्ते केवल सफलता तक ही सीमित हैं?

निष्कर्षः इंसानियत की परीक्षा

राजपाल यादव का मामला केवल कर्ज का मामला नहीं है। यह उस संवेदनशीलता की परीक्षा है, जो किसी भी समाज और उद्योग को महान बनाती है।

आज जरूरत है कि हम यह सोचें-

हँसाने वाले कलाकार के आँसू अगर हमें दिखाई नहीं देते,

तो कहीं न कहीं हमारी संवेदनाएं ही खो गई हैं।

ग्लैमर की दुनिया में भी इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए।

और अगर एक कलाकार यह कहने को मजबूर हो जाए कि "कोई साथ नहीं है," तो यह सिर्फ उसकी नहीं, पूरे सिस्टम की हार है।

गोपाल गावंडे

मुख्य संपादक, रणजीत टाइम्स

(संपादकीय विशेष)

अफसरशाही आगे आदिवासी हारा PM आवास की जगह झोपड़ी जीने का सहारा

प्रदीप सिंह बघेल

अनूपपुर। हर इंसान का सपना होता है कि उसके सिर पर एक पक्की छत हो, एक ऐसा घर जहां वह सम्मान और सुकून के साथ जीवन जी सके। इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, ताकि गरीब, वंचित और आदिवासी परिवारों को उनका आशियाना मिल सके। लेकिन जमीनी हकीकत कई जगह इस योजना की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसा ही एक मामला शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के बरगंवा अमलाई नगर परिषद क्षेत्र से सामने आया है, जहां बैगा आदिवासी परिवार आज भी छत के बिना जीवन गुजारने को मजबूर हैं।

बरगंवा अमलाई नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1, 2 और 5 में बड़ी संख्या में बैगा समुदाय के लोग निवासरत हैं। सरकार की योजनाओं में जिन्हें सबसे अधिक प्राथमिकता देने की बात कही जाती है, वही बैगा परिवार आज भी कच्ची और जर्जर झोपड़ियों में रहने को विवश हैं। बारिश में छत से टपकता पानी, गर्मी में झुलसाती धूप और सर्दियों में कंपकंपाती ठंड इनके रोज़मर्रा के

जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इन्हीं में से एक हैं राम प्रसाद बैगा, जो अपनी बुजुर्ग मां के साथ एक टूटी-फूटी झोपड़ी में रहते हैं। मजदूरी कर परिवार चलाने वाले राम प्रसाद वर्षों से पीएम आवास के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर काटने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। उनकी मां की आंखों में आज भी एक ही सपना है। मरने से पहले अपने सिर पर एक पक्की छत देखना।

दर्दनाक पहलू यह है कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में ऐसे प्रभावशाली लोगों को पीएम आवास का लाभ मिल गया है, जिनके पास पहले से पक्के मकान, गाड़ियां और संसाधन मौजूद हैं। जबकि वास्तविक हकदार बैगा परिवार आज भी दर-दर भटक रहे हैं। बैगा समाज के लोग अब संभागीय मुख्यालय तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अफसरशाही की चुप्पी उनकी उम्मीदों को तोड़ती जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सच में जरूरतमंद बैगा परिवारों तक पहुंचेगा, या फिर ये सपने फाइलों में ही दबकर रह जाएंगे। बैगा परिवारों की पथराई आंखें आज भी अपने हक के आशियाने का इंतजार कर रही हैं।

सुधीर पंडित जी के बेटे अथर्व को क्षिप्रा के पास से पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है

पं. दीनदयाल उपाध्यायः एकात्म मानवदर्शन के प्रणेता और समर्थ भारत निर्माण के चिंतक : डॉ. मोहन यादव

रणजीत टाइम्स

व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का मार्ग दिखाने वाले, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में कोटिशः नमन। पं. दीनदयाल जी का जीवन भारत राष्ट्र को दिशा देने वाला प्रकाश स्तंभ है। वे एक ऐसे ऋषि राजनेता थे जो समाज, संस्कृति और राष्ट्र के समग्र उत्थान के लिए समर्पित रहे। उन्होंने राजनीति को राष्ट्रधर्म की साधना का माध्यम माना। उनका स्पष्ट मत था कि स्वतंत्र भारत की यात्रा भारतीय दर्शन, संस्कृति और परंपरा के अनुरूप होनी चाहिए।

पं. दीनदयाल जी ने राजनीतिक चिंतन को भारतीय मूल्यों से जोड़ते हुए एकात्म मानव दर्शन का सूत्र दिया। इसमें व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सृष्टि के बीच समन्वय और संतुलन समाहित है। यह जीवन और संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में पिरोता है। यही दर्शन व्यष्टि से समष्टि की रचना करता है। इसमें श्रीकृष्ण के वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से लेकर आज के वैश्विक परिदृश्य का समावेश है।

पं. दीनदयाल जी भारत के भविष्य की कल्पना चतुर्पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पर की। उनका विश्वास था कि इन चारों का संतुलन ही व्यक्ति और समाज को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। यदि व्यक्ति और समाज को विकास के समान अवसर दिए जाएँ, तो स्वावलंबी और समर्थ समाज का निर्माण संभव है। पं. दीनदयाल जी का मानना था कि राजनीति का अंतिम लक्ष्य सशक्त, समरस और स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण है। उनका विकास मॉडल केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक संतुलन का समावेश था। वे चाहते थे कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, तभी वह सच्चा विकास कहलाएगा। यही अंत्योदय का भाव है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस विकास पथ पर अग्रसर है, उसके मूल में पं. दीनदयाल जी का चिंतन है। विरासत से विकास, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और सबका साथ - सबका विकास, यह सभी एकात्म मानव दर्शन के आधुनिक रूप हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का संकल्प है कि वर्ष 2047, स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत को विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया जाए। यह संकल्प पं. दीनदयाल जी के स्वप्निल भारत की ही साकार अभिव्यक्ति है।

मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण की परिकल्पना को मूर्तरूप देने की दिशा में प्रदेश के प्रत्येक अंचल को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के हर क्षेत्र की क्षमता, मेधा और दक्षता को अवसर प्रदान करने के लिए जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का नवाचार किया गया, वहीं भोपाल में संपन्न हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से स्थानीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। निवेश के लिये हमने यूके, जर्मनी, जापान और दावोस आदि यात्राएं कीं और हैदराबाद, कोयंबटूर सहित मुंबई में रोड-शो के माध्यम से उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। यह क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर तक उद्योग को जोड़ने का पहला सशक्त प्रयास है। मुझे यह बताते हुए संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन को व्यवहार में उतारने का प्रयत्न किया जा रहा है। समरस, संवेदनशील और उत्तरदायी शासन के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं और विकास के लक्ष्य धरातल पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश में गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा शक्ति और नारी सशक्तिकरण को केन्द्र में रखकर 4 मिशन के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इससे समाज के सभी वर्गों के कल्याण का लक्ष्य पूर्ण होगा।

पं. दीनदयाल जी ने आर्थिक विकास के लिए कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार समाज, सुरक्षा एवं सेवा का एक स्पष्ट और व्यावहारिक क्रम बताया। इस क्रम में कृषि प्रधान देश भारत में खेती को प्रथम स्थान देने की आवश्यकता व्यक्त की। उनका मानना था यदि देश में कृषि सुदृढ़ होगी, तो किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण जीवन में स्थिरता आएगी और उद्योगों को कच्चा माल एवं श्रम दोनों सहज रूप से उपलब्ध होगा। इससे किसान, उपभोक्ता और समाज तीनों का संतुलन बना रहेगा। पं. दीनदयाल जी खेती की मजबूती और किसानों की समृद्धि को समग्र विकास का आधार मानते थे। मुझे यह बताते हुए संतोष है कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में किसानों के स्वाभिमान, सुरक्षित जीवन और आत्मनिर्भरता को केन्द्र में रखकर वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई, भंडारण और बाजार तक बेहतर पहुंच के माध्यम से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाएगा। कृषि आजीविका के साधन के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2025-26 किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। मध्यप्रदेश में पार्वती-कालीसिंध-चंबल तथा केन-बेतवा नदी लिंक राष्ट्रीय परियोजना सहित ताप्ती ग्राउंड वॉटर रिचार्ज मेगा परियोजना से प्रदेश के 25 जिलों में 16 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त कृषि रकबा सिंचित होगा। प्रदेश के किसानों के समग्र कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठाया जायेगा। प्रदेश में श्रीअन्न, सरसों और चना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। इससे श्रीअन्न का उत्पादन और पोषण सुरक्षा को नई ऊंचाई मिलेगी। इन केंद्रों के जरिए फसलों की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रदेश के 30 लाख से अधिक किसानों को अगले तीन साल में सोलर पॉवर पम्प दिये जायेंगे। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 65 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हैक्टेयर किये जाने का लक्ष्य है।पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वाभिमानी, स्वावलंबी और विश्व कल्याण में अग्रणी भारत की कल्पना की थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका जीवन और दर्शन हम सबको राष्ट्रधर्म के पथ पर निरंतर अग्रसर करता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के अमर साधक पं. दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर पुनः कोटिशः वंदन।
(लेखक, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

देपालपुर में हाटकेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न

रणजीत टाइम्स

देपालपुर हाटकेश्वर कॉलोनी स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर में तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का बुधवार को विधिवत समापन हुआ।

इस अवसर पर भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी, कछुए और मां पार्वती की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। महोत्सव के अंतिम दिन प्रातः 8 बजे से दिग्होम एवं प्रासाद स्नपन प्रारंभ हुआ। दोपहर 12:30 बजे वैदिक ऋचाओं के गान और मंत्रोच्चार के बीच मुख्य कलश स्थापना, कीर्ति स्तंभ, ध्वज दंड तथा नई प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई। इसके उपरांत श्रीफल होम के साथ यज्ञ पूर्ण किया गया। प्रतिष्ठा के बाद हाटकेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से भर उठा। आचार्य पंडित राजेश शास्त्री के नेतृत्व में यज्ञ सम्पन्न हुआ। यजमान के रूप में अतुल नागर, सुबोध नागर, हेमंत नागर, अजय नागर, जेपी नागर और वीरेंद्र गौड़ ने लाभ प्राप्त किया। मंदिर निर्माण का कार्य सूर्य प्रकाश माणकलाल नागर द्वारा करवाया गया। यह आयोजन धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक बनकर नगरवासियों के लिए अविस्मरणीय रहा।

ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल

रणजीत टाइम्स

देपालपुर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), भारत सरकार के अंतर्गत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी इंदौर में आयोजित पापड़ एवं अचार निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन किया गया।

यह प्रशिक्षण ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोज़गार के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का सफल संचालन संकाय सदस्य श्रीमती रूपा कौशल द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पापड़ एवं अचार निर्माण की आधुनिक तकनीकें, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लागत निर्धारण और विपणन से संबंधित व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। समापन सह-सम्मेलन आरसेटी परिसर, भेसले पंचायत में आयोजित हुआ, जिसमें संस्थान के सभी स्टाफ

सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर निदेशक, आरसेटी इंदौर ने प्रशिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और स्वरोज़गार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु मार्गदर्शन दिया। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से आह्वान किया कि वे प्राप्त कौशल का उपयोग कर स्वयं का उद्यम प्रारंभ करें और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाएं। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और आरसेटी इंदौर द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण हेतु आभार व्यक्त किया। यह पहल ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोज़गार को बढ़ावा देनेओर महिलाओं-युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

बांग्लादेश में उबलते सियासी घमासान के बीच चुनाव की तैयारी

संवेदनशील मतदान केंद्रों के बीच लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा

ढाका, एजेंसी

बांग्लादेश महीनों से उबलते सियासी घमासान के बाद अब फैसले की दहलीज पर खड़ा है। कल यानी 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव केवल सरकार चुनने की कवायद नहीं, बल्कि देश की कानून-व्यवस्था, लोकतंत्र और स्थिरता की भी अग्निपरीक्षा हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का हालिया बयान इस चुनाव और मतदान को लेकर सियासी टकराव और इसकी गंभीरता को उजागर कर रहा है। बांग्लादेश चुनाव आयोग का मानना है कि देश के आधे से ज्यादा मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

साथ ही इन केंद्रों पर खास निगरानी भी रखी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, करीब 90 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर सीसीवीटी कैमरे लगाए गए हैं। राजधानी ढाका में तैनात कई पुलिसकर्मी पहली बार बॉडी कैमरा पहनकर ड्यूटी करेंगे, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

जोखिम के आधार पर सुरक्षा

चुनाव आयुक्त अबुल फजल मोहम्मद सनाउल्लाह ने मंगलवार देर रात मीडिया को बताया कि चुनाव आयोग की सुरक्षा योजना जोखिम के आकलन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हर इलाके की स्थिति को देखकर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह चुनाव देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा तैनाती के साथ कराया जा रहा है और तकनीक का भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है।

पुलिस और सेना के अलग-अलग आंकड़े

पुलिस महानिरीक्षक बहादुरुल आलम ने बताया कि देश के करीब 43,000 मतदान केंद्रों में से 24,000 केंद्र उच्च या मध्यम स्तर के संवेदनशील हैं। पुलिस के अनुसार ढाका के 2,131 मतदान केंद्रों में से 1,614 केंद्र संवेदनशील हैं। हालांकि, सेना ने एक अलग मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ढाका शहर में केवल दो केंद्र ही जोखिम भरे हैं। ऐसे में इन आंकड़ों में अंतर को लेकर सवाल भी उठे हैं।

बांग्लादेश चुनाव में पहली बार बॉडी कैमरा

अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मी पहली बार बॉडी-वॉर्न कैमरा इस्तेमाल करेंगे। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। वहीं चुनाव आयुक्त सनाउल्लाह ने कहा कि चुनाव आयोग मौजूदा कानून-व्यवस्था से काफी हद तक संतुष्ट है। उनका कहना है कि पहले के मुकाबले इस बार स्थिति कहीं बेहतर है।

12 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस बार के चुनाव में कुल 12 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। पहली बार वोट देने वाले मतदाता करीब 3.58 प्रतिशत हैं। खास बात यह भी है कि इस बार चुनाव एक जनमत संग्रह के साथ हो रहे हैं, जिसमें 84 बिंदुओं वाले जटिल सुधार प्रस्ताव पर जनता की राय ली जा रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी (जो पहले बीएनपी की सहयोगी थी) के बीच कड़ा मुकाबला भी माना जा रहा है।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में

छठी बार कोर्ट को उड़ाने की धमकी, ईमेल से फैली दहशत

पटना, एजेंसी

पटना सिविल कोर्ट को सुबह एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी और सूचना मिलते ही प्रशासन ने एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा लिया। अदालती कार्यवाही रोक दी गई और सुरक्षा कारणों से किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि एक बजे रात को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आॅफिस के मेल पर आरडीएक्स प्लांट किये जाने की बात लिखी है। कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता भी पहुंचकर जांच कर रही है। जांच के बाद 12 बजे से अदालत की कार्यवाही आरंभ होगी।

घटना की जानकारी मिलते ही पीरबहोर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को भी जांच में लगाया गया है, जो हर कमरे, गलियारे और पार्किंग क्षेत्र की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके।

साइबर जांच में जुटी एजेंसियां

धमकी ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल को भी सक्रिय कर दिया गया है और आईपी एड्रेस सहित डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बार-बार इस तरह की धमकी कौन और किस मकसद से भेज रहा है। फिलहाल कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच पूरी होने तक स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

सीएम हिमंत ने दी कांग्रेस को चेतावनी

'मेरी अवैध जमीन की सूची कोर्ट में जमा करो, नहीं तो 500 करोड़ रुपये दो'

नई दिल्ली। 'भूमि हड़पने' के आरोपों पर मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी और कहा, मेरी 12,000 बीघा 'अवैध भूमि' की सूची अदालत में जमा करें, अन्यथा मुझे 500 करोड़ रुपये दें। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को दावा किया कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर जुबानी हमला बोला, गोगोई का 2013 के पाकिस्तान दौरे के दौरान 'बिना वीज़ा के रावलपिंडी जाने की बात मानना' यह साबित करता है कि वह पड़ोसी देश में 'स्टेट गेस्ट' थे।

बोंगाईगांव में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा, 'गोगोई ने खुद कहा है कि वह रावलपिंडी गए थे और उन्होंने ये भी माना है कि वह बिना वीज़ा के गए थे, तो वह ज़रूर पाकिस्तानी सेना या पुलिस की गाड़ी में गए होंगे। अगर वह बिना वीज़ा के गए हैं, तो इसका मतलब है कि वह स्टेट गेस्ट थे और मेरे बताने से पहले ही उन्होंने यह खुद बता दिया और वह वीडियो क्लिप कोर्ट में पेश करने के लिए काफी है। गौरव गोगोई ने कहा था, दिसंबर 2013 में पड़ोसी देश की 10 दिन की ट्रिप के दौरान वह अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान में तक्षशिला गए थे और इसके लिए उन्होंने इजाज़त ली थी।

कार-ट्रक की भीषण टक्कर, छह लोगों मौत

दौसा। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 5 सगे भाई और उनके एक दोस्त की मौत हो गई। सभी युवक शादी-समारोह से लौटकर घर जा रहे थे। जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर कैलाई गांव के पास रात करीब 11 बजे उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई, डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ जा रहे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हादसे से कुछ घंटे पहले सभी दोस्त शादी समारोह में साथ बैठकर खाना खा रहे थे और उन्होंने एक साथ फोटो भी क्लिक करवाई थी। इसके बाद सभी एक ही कार में सवार होकर घर के लिए रवाना हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।

उम्रकैद की सजा घटाकर 12 साल की

रेप केस के दोषी ने गांधी पर लिखा निबंध, कोर्ट ने कम कर दी सजा

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से रेप के दोषी एक आदमी की उम्रकैद की सजा घटाकर 12 साल कर दी है। कोर्ट ने उसकी कम उम्र, लंबे समय तक जेल में रहने और जेल में सुधार की कोशिशों को ध्यान में रखते हुए यह सजा दी है। सुधार की कोशिशों में महात्मा गांधी पर एक निबंध प्रोग्राम में हिस्सा लेना भी शामिल है।

जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस संदेश पाटिल की बेंच ने 2 फरवरी के अपने आदेश में 2016 के जुर्म में आदमी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन कहा कि उसे दी गई उम्रकैद की सजा कम की जानी चाहिए। बेंच ने यह आदेश दोषी की अपील पर दिया, जिसमें उसने स्पेशल POCSO कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि अपराध के समय दोषी की उम्र 20 साल थी, उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वह दिसंबर 2016 से हिरासत में था और उसे COVID-19 महामारी के दौरान भी रिहा नहीं किया गया था। बेंच ने जेल की पढ़ाई-लिखाई की एक्टिविटीज में उसके हिस्सा लेने वाले सर्टिफिकेट पर भी विचार किया, जिसमें एक निबंध कॉम्पिटिशन और महात्मा गांधी के विचारों पर स्टडी करने वाला एक प्रोग्राम शामिल था। जुर्म की गंभीरता के हिसाब से इन सुधार वाले फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने कहा, 'हमारी राय में 12 साल की सजा इंसाफ के लिए सही होगी।'

श्रद्धांजलि

दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि: राजनाथ-शाह ने भी नमन किया

पीएम मोदी बोले- उनके सिद्धांत हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक

नई दिल्ली, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों को देश की हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बताया। सर्वस्व समर्पण उस चेतना की अभिव्यक्ति है, जिसमें राष्ट्र और मानवता सर्वोपरि होती है। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी इसी भावना से देश के जन-जन को सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र का विकास: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता व महान राष्ट्रचिंतक बताया। शाह ने कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र के विकास का मापदंड है और यह विचार देने वाले दीनदयाल जी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।

कर्मयोगी और महान विचारक रहे उपाध्याय: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें निस्वार्थ कर्मयोगी और महान विचारक बताते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से दिया गया अंत्योदय का मंत्र समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना आज भी विकसित भारत के निर्माण की बुनियाद है।

सबका साथ, सबका विकास की भावना उनकी विचारधारा से आई: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे पंडित उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास की भावना उनकी विचारधारा की जीवंत अभिव्यक्ति है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने दार्शनिक सिद्धांत के लिए हैं प्रसिद्ध

पंडित दीनदयाल उपाध्याय (1916-1968) एक प्रमुख राजनीतिक चिंतक, अर्थशास्त्री और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से थे। वे अपने दार्शनिक सिद्धांत 'एकात्म मानव दर्शन' के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं।उनकी विचारधारा का मूल आधार यह था कि विकास केवल भौतिक प्रगति तक सीमित न रहकर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन और सामंजस्य पर जोर दिया। उनके अनुसार, आर्थिक नीतियों का लक्ष्य केवल उत्पादन और उपभोग बढ़ाना नहीं, बल्कि मानव के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। वे 1968 में अपने असामयिक निधन तक भारतीय जनसंघ का नेतृत्व करते रहे।

पुण्यतिथि पर विशेष

दीनदयाल उपाध्याय : एकात्म मानववाद के प्रणेता विचारक, अर्थशास्त्री और पत्रकार

हर्षवर्धन पांडे
स्तंभकार

पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय विचारक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, लेखक, पत्रकार, संपादक थे। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी एक दौर में रहे। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्होंने भारत द्वारा पश्चिमी धर्म निरपेक्षता का विरोध किया। उन्होनें लोकतंत्र की अवधारणा को सरलता से स्वीकार किया लेकिन पश्चिमी कुलीनतंत्र, शोषण और पूंजीवादी मानने से साफ़ इंकार कर दिया। पंडित जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन जनता की सेवा में लगा दिया। भारतीय पत्रकारिता ने सदैव राष्ट्रवाद को पल्लवित करने का निर्वहन किया है। पत्रकारिता में राष्ट्रवादी स्वर को गति देने वाले पत्रकारों में पं. दीनदयाल उपाध्याय का नाम आदर के साथ लिया जाता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक नेताओं ने पत्रकारिता के प्रभावों का उपयोग अपने देश को स्वतंत्रता दिलाकर राष्ट्र के पुनर्निमाण के लिए किया। विशेषकर हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषायी पत्रकारों में खोजने पर भी ऐसा सम्पादक शायद ही मिले जिसने अर्थोपार्जन के लिए पत्रकारिता का अवलम्बन किया हो।

दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितम्बर, 1916, नगला चन्द्रभान, मथुरा, उत्तर प्रदेश में एक मध्यम वर्गीय प्रतिष्ठित हिंदू परिवार में हुआ था। उनके परदादा का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था, जो एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। उनके पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय तथा मां का नाम रामप्यारी था। उनके पिता जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत थे। दीनदयाल ने कम उम्र में ही अनेक उतार-चढ़ाव देखा, परंतु अपने दृढ़ निश्चय से जिन्दगी में आगे बढ़े। उन्होंने सीकर से हाईस्कूल की परीक्षा पास की जन्म से बुद्धिमान और उज्ज्वल प्रतिभा के धनी दीनदयाल को स्कूल और कालेज में अध्ययन के दौरान कई स्वर्ण पदक और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। दीनदयाल इण्टरमीडिएट की पढ़ाई के लिए 1935 में पिलानी चले गए। 1937 में इण्टरमीडिएट बोर्ड के परीक्षा में बैठे और न केवल समस्त बोर्ड में सर्वप्रथम रहे वरन सब विषयों में विशेष योग्यता के अंक प्राप्त किए। बिडला कॉलेज का यह प्रथम छात्र था, जिसने इतने सम्मानजनक अंको से परीक्षा पास की थी। सीकर महाराजा के समान ही घनश्याम दास बिड़ला ने एक स्वर्ण पदक, 10रू मासिक छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों आदि के खर्च के लिए 250 रू प्रदान किए। सन 1939 में सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर से प्रथम श्रेणी में बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। एम.ए. अंग्रेजी साहित्य में करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया। इसके पश्चात उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की लेकिन आम जनता की सेवा की खातिर उन्होंने इसका परित्याग कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय की पत्रकारिता में भी अग्रणी भूमिका रही है। अपने राष्ट्रवाद के विचारों को जनमानस तक प्रेषित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ने पत्रकारिता को माध्यम बनाया था। पत्रकारिता किस प्रकार से जनमत निर्माण करने में सहायक होती है, यह दीनदयाल जी ने बखूबी समझा था। एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय ने गांधी के विचार को पुनःव्याख्यायित करते हुए अंत्योदय की बात की। दीनदयाल जी ने राष्ट्रहित व चिंतन के विचारों को पत्रकारिता के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक कुशल पत्रकार और बेहतर संचारक थे। अपनी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए पत्रों

का संपादन, प्रकाशन, स्तंभ लेखन, पुस्तक लेखन उनकी रुचि का विषय था। उन्होंने लिखने के साथ-साथ बोलकर भी एक प्रभावी संचारक की भूमिका का निर्वहन किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लोक कल्याण को ही पत्रकारिता का प्रमुख आधार माना। दीनदयाल के पास समाचारों का न्यायवादी एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण था। उनके लेखों, उपन्यासों व नियमित कॉलमों में निष्पक्ष आलोचना, उचित शब्दों का प्रयोग और सत्यपरक खबरों को ही मानवता के अनुकूल मिलता है। राष्ट्र भक्ति को पल्लवित करने की भावना को साकार स्वरूप देने का श्रेय उंनकी पत्रकारिता को भी जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को साहित्य से एक अलग ही लगाव था शायद इसलिए दीनदयाल उपाध्याय अपनी तमाम ज़िन्दगी साहित्य से जुड़े रहे। उनके हिंदी और अंग्रेजी के लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। साहित्य से लगाव इतना की उन्होंने केवल एक बैठक में ही चंद्रगुप्त नाटक लिख डाला था। भारत विभाजन के दौर में भयानक रक्तपात हुआ। देश, भारत को एक राष्ट्र मानने तथा भारत को द्विराष्ट्र मानने वाले में बंट गया। इसी हिंसाचार ने महात्मा गांधी को भी लील लिया। उनकी जघन्य हत्या हुई। देश के विभाजन की विभीषिका ने दीनदयाल जी को बहुत आहत किया। उन्होनें इस पर प्रखरतापूर्वक अपना पक्ष रखा। पंडित दीनदयाल के अनुसार अखण्ड भारत देश की भौगोलिक एकता का ही परिचायक नहीं अपितु जीवन के भारतीय दृष्टिकोण का परिचायक है जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है। अतः हमारे लिए अखण्ड भारत राजनैतिक नारा नहीं है, बल्कि यह तो हमारे संपूर्ण जीवनदर्शन का मूलाधार है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा एकात्म मानववाद का विकल्प एवं अंत्योदय का विचार उस कालखंड में दिया गया जब देश में समाजवाद, साम्यवाद जैसी आयातित विचारधाराओं का बोलबाला था। भारत में भारतीयता को पुनर्जीवित करने वाली विचारधारा की बजाय समाजवाद एवं साम्यवाद जैसी आयातित विचारधाराओं का बोलबाला होना भारतीयता के लिए अनुकूल नहीं था। पंडित जी ने भारत की समस्या को भारत के सन्दर्भों में समझकर उसका भारतीयता के अनुकूल समाधान देने की दिशा में एक युगानुकुल प्रयास किया। दीनदयाल जी ने अपने चिन्तन में आम मानव से जुड़ी जिन चिंताओं और समाधानों को समझाने का प्रयास आज से दशकों पहले किया था। सही मायनों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पत्रकारिता को भी इसी दृष्टि से एक नई दिशा दी। वे स्वयं कभी संपादक या औपचारिक संवादाता नहीं रहे। उन्होंने संपादकों और संवाददाताओं का सुखद सानिध्य प्राप्त किया। तभी संपादक व पत्रकार उन्हें सहज ही अपना मित्र एवं मार्गदर्शक मानते थे। पत्रकार के नाते पंडित जी का योगदान अनुकरणीय था। दीनदयाल जी उस युग की पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व करते थे जब पत्रकारिता एक मिशन होने के कारण आदर्श थी व्यवसाय नहीं थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक नेताओं ने पत्रकारिता के प्रभावों का उपयोग अपने देश को स्वतंत्रता दिलाकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए किया। ऐसा सम्पादक शायद ही मिले जिसने अर्थोपार्जन के लिए पत्रकारिता का अवलंबन किया हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि पत्रकारिता करते समय राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और स्वदेश के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में जो मूल्य और मानदंड स्थापित किया उसकी दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। दीनदयाल उपाध्याय का पत्रकारीय चिंतन राष्ट्रवादी और भारतीय जीवन मूल्यों की विचारधारा से जुड़ता है। पत्रकारिता के आधार पर उन्होंने राष्ट्र को समझने तथा भारतीय अस्मिता को लोगों तक पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

संसद का बजट सत्र ठप, कांग्रेस को अपनी भूमिका पर गंभीर आत्ममंथन की जरूरत

कांतिलाल मांडोत
स्तंभकार

संसद का बजट सत्र देश की आर्थिक दिशा तय करने का सबसे महत्वपूर्ण मंच होता है, लेकिन जब यही मंच हंगामे, नारेबाजी और रणनीतिक अवरोध का अखाड़ा बन जाए, तो सवाल सिर्फ कार्यवाही के ठप होने का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के क्षरण का भी उठता है। हालिया घटनाक्रम में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, प्रश्नकाल का बार-बार स्थगन और विपक्ष का निरंतर विरोध, इसी चिंता को गहरा करता है। इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस की भूमिका पर गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है।

लोकसभा में विपक्ष का अधिकार बहस करना, सवाल उठाना और सरकार को जवाबदेह ठहराना है। यह अधिकार संविधान और संसदीय परंपराओं से सुरक्षित है। लेकिन जब यह अधिकार सदन को चलने ही न देने की जिद में बदल जाए, तो वह लोकतंत्र की मजबूती के बजाय उसकी कमजोरी का संकेत बन जाता है। बजट सत्र

के लगातार दिनों तक बाधित रहने से आम जनता के मुद्दे, आर्थिक नीतियों पर चर्चा और विकास से जुड़े सवाल पीछे छूट जाते हैं। कांग्रेस, जो स्वयं को लोकतंत्र की प्रहरी बताती है, यदि उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करती दिखे, तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई असाधारण बात नहीं है। संसदीय इतिहास में यह प्रक्रिया पहले भी अपनाई गई है। लेकिन इस कदम का औचित्य तभी बनता है, जब यह संसदीय मर्यादा और ठोस तर्कों के साथ उठाया जाए। मौजूदा मामले में विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। यदि यह सच है, तो इसका समाधान भी संसदीय संवाद और नियमों के तहत होना चाहिए। सदन के भीतर नारेबाजी, वेल में आकर हंगामा और बार-बार कार्यवाही ठप कराना, किसी भी तरह से समाधान नहीं है।

कांग्रेस का रवैया यहां विरोध से अधिक टकराव का नजर आता है। राहुल गांधी को बोलने देने की मांग को लेकर पूरा सत्र बाधित करना, जबकि देश की आर्थिक नीतियों पर चर्चा लंबित हो, यह दर्शाता है कि पार्टी प्राथमिकताओं को लेकर भ्रमित है। लोकतंत्र में व्यक्ति से बड़ा संस्थान होता है। संसद किसी एक नेता का मंच नहीं, बल्कि 140 करोड़ नागरिकों की आवाज का प्रतिनिधि सदन है। यदि किसी नेता को बोलने में आपत्ति है, तो उसके लिए नियम, अध्यक्ष और संसदीय समितियां मौजूद हैं। सत्र को ही ठप कर देना, लोकतांत्रिक दबाव नहीं, बल्कि राजनीतिक हठधर्मिता है। कांग्रेस का इतिहास बताता है कि जब वह सत्ता में रही, तब विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप उस पर भी लगे। ऐसे में आज नैतिक ऊंचाई का दावा करना, बिना आत्मालोचना के, खोखला लगता है। संसदीय परंपराएं दोतरफा जिम्मेदारी मांगती हैं। सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए, लेकिन विपक्ष का भी कर्तव्य है कि वह सदन की गरिमा बनाए रखे। हाथ जोड़कर बजट पर चर्चा की अपील करना किसी मंत्री की कमजोरी नहीं, बल्कि संसदीय परंपरा को बचाने का प्रयास है। इसके बावजूद हंगामा जारी रहना, कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को उजागर करता है।

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति अस्पष्ट दिखती है। एक ओर प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है, दूसरी ओर प्रमुख नेता खुद उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। यह दोहरा संदेश पार्टी की आंतरिक असमंजस को दर्शाता है। यदि स्पीकर सचमुच पक्षपात कर रहे हैं, तो पार्टी को एकजुट और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए था। लेकिन यहां यह कदम अधिक प्रतीकात्मक विरोध जैसा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य समाधान नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाना है। संसद में महिला सांसदों के साथ हुई घटनाओं, बैनर और पोस्टर की राजनीति, और पुस्तक विवाद जैसे मुद्दों को जिस तरह तूल दिया गया, उसने मूल प्रश्नों को हाशिए पर धकेल दिया। देश महंगाई, रोजगार, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट बहस चाहता है। लेकिन कांग्रेस का फोकस बार-बार ऐसे विवादों पर रहा, जिनसे सदन का समय नष्ट हुआ। यह रवैया न तो विपक्ष की परिपक्वता दिखाता है और न ही लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता।लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन रचनात्मक विरोध उससे भी अधिक जरूरी है। कांग्रेस यदि सचमुच जनता की आवाज बनना चाहती है, तो उसे सड़क की राजनीति को संसद के भीतर दोहराने से बचना होगा। संसद संवाद का मंच है, संघर्ष का नहीं। यहां तर्क, तथ्य और नीति से सरकार को घेरा जाता है, न कि शोर और अवरोध से। हर बार सदन ठप कर देना आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन इससे न तो जनता का भरोसा बढ़ता है और न ही लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं।

अंततः सवाल यह नहीं है कि कौन जीता या हारा, बल्कि यह है कि संसद चली या नहीं। बजट सत्र का समय अमूल्य होता है। इसे बाधित कर कांग्रेस ने न सिर्फ सरकार को, बल्कि देश को नुकसान पहुंचाया है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सत्ता को असहज करना नहीं, बल्कि उसे जवाबदेह बनाना है। इसके लिए सदन का चलना अनिवार्य है। यदि कांग्रेस इस मूल सिद्धांत को नहीं समझती, तो उसका विरोध लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि अवरोधकारी राजनीति के रूप में ही देखा जाएगा।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

अवेयरनेस

ब्लड डोनेट करने से एक्टिव रहता है बोन मैरो , नई ब्लड सेल्स भी बनती हैं

रक्तदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि आपका डोनेट किया हुआ खून किसी की जिंदगी बचा सकता है। ब्लड डोनेट करना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। हालांकि कई लोगों के मन में यह डर बना रहता है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में खून की कमी हो सकती है या कमजोर आ सकती है। इस डर की वजह से कई लोग हेल्दी होने के बावजूद ब्लड डोनेट करने से बचते हैं।

डॉक्टर्स का साफ कहना है कि ब्लड डोनेट करना सेहत के लिए सुरक्षित है और इससे शरीर को फायदे भी मिल सकते हैं। हेल्दी लोगों को 2-3 महीने में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए।

सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉ. सोनिया रावत के अनुसार ब्लड डोनेट करना सेहत के लिए पूरी तरह सेफ है। एक बार में लगभग 350 से 450 मिलीलीटर ब्लड लिया जाता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के खून की मात्रा का छोटा सा हिस्सा होता है। ब्लड डोनेशन के बाद शरीर में मौजूद प्लाज्मा 24 से 48 घंटे के भीतर दोबारा बन जाता है, जबकि रेड ब्लड सेल्स की भरपाई कुछ हफ्तों में हो जाती है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदान से खून की कमी नहीं होती है। सभी लोगों को ब्लड डोनेशन से जुड़ी गलतफहमी से बचना चाहिए।

डॉक्टर ने बताया कि समय-समय पर ब्लड डोनेट करने से शरीर में नई ब्लड सेल्स का निर्माण तेज होता है। इससे बोन मैरो एक्टिव रहता है और नई रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। कई रिसर्च में यह भी पता चला है कि ब्लड डोनेशन से हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। कुछ लोगों को हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह टेंपरी होती है। पर्याप्त पानी पीने, आयरन से भरपूर डाइट लेने और आराम करने से आप नॉर्मल महसूस करेंगे। आमतौर पर पुरुष हर 3 महीने और महिलाएं हर 4 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकती हैं। एक्सपर्ट की मानें तो हर व्यक्ति ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। जिन लोगों को एनीमिया, इंफेक्शन, गंभीर बीमारी हो, उन्हें ब्लड डोनेशन की सलाह नहीं दी जाती है। हाल ही में सर्जरी कराने वाले लोगों को भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। आमतौर पर रक्तदान से पहले हीमोग्लोबिन और सामान्य स्वास्थ्य की जांच की जाती है, ताकि डोनर की सेहत का आकलन हो सके।

न्यूयॉर्क की हडसन नदी पर बर्फ की सफेद संगमरमर की चादर

न्यूयॉर्क। भीषण शीत लहर के कारण न्यूयॉर्क की हडसन नदी में बर्फ की मोटी परत जम गई है। नदी के किनारों, विशेष रूप से मैनहट्टन के पश्चिमी तट पर, बर्फ की मोटी सिल्लियां तैरती और जमती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे यह दृश्य किसी सफेद संगमरमर की चादर जैसा लग रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पिछले कई वर्षों में बर्फ की सबसे अधिक मात्रा है, जो 1888 और 1947 जैसी ऐतिहासिक ठंड की याद दिलाती है। वहीं इन दिनों शहर की सड़कों पर भी जगह-जगह बर्फबारी से बर्फ के ऊँचे-ऊँचे ढेर जमा हो गए हैं ।

'देश को बेच दिया...' संसद में राहुल गांधी के आरोपों पर क्या बोली बीजेपी?

नई दिल्ली। यूं तो ट्रेड डील पर बुधवार सुबह ही अमेरिका की ओर से सफाई आ गई है लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका से ट्रेड डील को 'संपूर्ण सरेंडर' करार देते हुए कहा कि सरकार ने 'भारत माता को बेच दिया है। पीएम मोदी पर दबाव में डील पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, ऐसी डील पर तब तक हस्ताक्षर करेगा जब तक उस पर कोई दबाव न हो।'

ट्रेड डील को राहुल गांधी ने 'संपूर्ण सरेंडर' कहा

सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दुखद है कि भाजपा के वित्तीय ढांचे को बचाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के हितों का सरेंडर किया गया है और किसानों की रोजी-रोटी, कपड़ा, देश की ऊर्जा सुरक्षा से लेकर डाटा और उसका सोर्स कोड जैसे बेहद अहम क्षेत्रों को गिरवी रख दिया गया है।

लोकसभा में बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बुधवार को राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट की विद्या का हवाला देते हुए आरोप

लगाया कि अमेरिका ने पीएम मोदी की गर्दन पकड़ रखी (चोकहोल्ड) है और इसीलिए हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने वाले इस डील पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी पर दबाव में डील साइन करने का आरोप- राहुल गांधी ने सरकार के निकट माने जाने वाले एक बड़े अद्योगिक घराने पर अमेरिका में दर्ज मामले और विवादित एपस्टीन फाइल्स के संदर्भ में अनिल अंबानी तथा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का नाम लेते हुए आरोप लगाया जिस पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रीजीजू और सत्तापक्ष के एतराज के बाद सभापति जगदंबिका पाल ने रिकार्ड से हटाने की बात कही।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के वर्तमान उथल-पुथल वाले भू-राजनीतिक परिश्य में हमारी 140 करोड़ की आबादी, खाद्य सुरक्षा, डाटा तथा ऊर्जा सुरक्षा चीन तथा अमेरिका के बीच सुपर पावर की होड़ में सबसे बड़ी ताकत है। मगर इस ताकत को पीएम ने अमेरिका को सौंप दिया है। डेटा सौंपने के साथ डिजिटल ट्रेड नियमों पर कंट्रोल छोड़ दिया है। कोई डेटा लोकलाइजेन नहीं है, कोई सोर्स कोड डिस्क्लोजर नहीं है और 20 साल का टैक्स हॉलीडे देते हुए हमारी सबसे कीमती संपत्ति ट्रंप को सौंप दी गई है।

किसानों, ऊर्जा, डेटा सुरक्षा को गिरवी रखने का दावा

कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिकी मशीनी हाइटेक खेती के आगे हमारे किसानों को उसके रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है और हमारे टेक्सटाइल पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाकर उसे खत्म किया गया है क्योंकि बांग्लादेश पर शून्य टैक्स है जो भारत के कपड़ा उद्योग को नष्ट कर देगा। इसी तरह हम रूस ईरान या जिससे चाहे तेल नहीं खरीद सकते और अमेरिका जिससे कहेगा उसी से खरीदना। ट्रेड डील पर सरकार को नसीहत देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आईएनडीआइए ब्लाक की सरकार होती तो हम राष्ट्रपति ट्रंप से कहते कि आपको अपने डालर को बचाना है तो हमारा डाटा सबसे बड़ी संपत्ति है इसको मानना होगा। आइएनडीआइए की सरकार होती तो ऊर्जा सुरक्षा पर कोई दबाव स्वीकार नहीं करते, साथ ही ट्रंप से कहते आपको अपने खेती-बाड़ी वाले वोटर बेस की रक्षा की जरूरत है मगर हम भी अपने किसानों की पूरी रक्षा करेंगे।

युवती ने परिजनों के साथ जाने से किया इनकार, नगदी-आभूषण ले जाने के आरोप से भी किया इंकार

इंदौर। खजराना थाना क्षेत्र में एक युवती के घर से चले जाने और नगदी व आभूषण ले जाने के आरोप का मामला सामने आया है। फरियादी भानु सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनकी पुत्री तनीषा 2 फरवरी को नवीन पिता रामलाल, निवासी दाऊद खेड़ी जिला खरगोन, के साथ घर से चली गई थी। परिजनों का आरोप है कि युवती अपने साथ घर में रखे 55 हजार रुपये नकद तथा करीब 2 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण भी ले गई। मामले की शिकायत खजराना थाने में की गई थी। बुधवार को युवती को खजराना थाने लाया गया, जहां उसने अपने माता-पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। साथ ही उसने नगदी व आभूषण ले जाने के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। अब देखना होगा कि पुलिस चोरी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज करती है या नहीं। फिलहाल खजराना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।